(c) and (d) The existing policy is under review. The Inter-Ministerial Committee has been set up for the purpose. The Committee have circulated a questionaire and also held zonal meetings with all the State Governments to elicit their views. The suggestions received from various State Governments are under examination by the Committee.

लोक अदालतों द्वारा की गई बैठकें

828. **श्री चिमन भाई महता :**
श्री रामसिंह भाई पातलीया
भाई राठवा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 14 फरवरी, 1986 की अवधि के दौरान गुजरात में तथा देश के अन्य भागों में लोक अदालतों द्वारा की गई बैठकों की संख्या कितनी है,

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन अदालतों में दायर किए गए मामलों की संख्या कितनी है तथा ये मामले किस प्रकार के हैं ;

(घ) ऐसी अदालतों द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या कितनी है तथा उसके द्वारा दिए गए न्याय-निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उपयुक्त अवधि के दौरान लोक अदालतें स्थापित की गई थीं;

(च) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां न तो ऐसी अदालतें स्थापित की गई हैं और न ही अब तक उनकी कोई बैठक हुई है ; और

(छ) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनकी लोक अदालतें स्थापित किए जाने तथा 1986 के दौरान उनकी बैठकें किए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) लोक अदालतों के कार्य का समन्वय विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है । समिति द्वारा भेजी गई जानकारी निम्नलिखित है :—

(क), (ख) और (ङ) उन राज्यों के नाम और उन राज्यों में लोक अदालत द्वारा की गई बैठकों की संख्या :—

क्रम० सं०	राज्य का नाम	जितनी लोक अदालतें हुई हैं उनकी संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	6
2	बिहार	3
3	गुजरात	1
4	हरियाणा	2
5	उड़ीसा	3
6	राजस्थान	3
7	तमिल नाडु	2
8	उत्तर प्रदेश	1

(ग) और (घ) अदालतों में फाइल और विनिश्चित किए गए मामलों की संख्या :—

राज्य का नाम	विनिश्चित मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2000
बिहार	2340
हरियाणा	5000 (लगभग)
उड़ीसा	490
राजस्थान	7720
उत्तर प्रदेश	9800

(गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के बारे में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इन मामलों में सिविल, दाण्डिक, वैवाहिक राजस्व और मोटर दुर्घटना आदि संबंधी दावे सम्मिलित हैं ।

लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के ब्यौरे संकलित नहीं किए गए हैं ।

(च) निम्नलिखित राज्य संघ/राज्यक्षेत्रों में लोक अदालतें नहीं लगी हैं :—

राज्य :—असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल । (वि०स०, स्कीम का०स० के पास महाराष्ट्र के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है) ।

संघ राज्यक्षेत्र :—

अण्डमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नागर हवेली, अरूणाचल प्रदेश, गोवा दमण और द्वीप, लक्षद्वीप, मिजोरम, चंडीगढ़ और पाण्डिचेरी ।

(छ) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का इस वर्ष इन अन्य राज्यों में भी लोक अदालतें लगाने का प्रस्ताव है ।

Substandard electrical appliances

829. SHRI RAM NARESH KUSH-WAHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the raids recently conducted by the Directorate of Industries, Delhi Administration, majority of the household electrical appliances sold in the major markets were found to b_e substandard and hazardous; and

(b) if so, what are the details thereof stating the action taken by Government against the dealers manufacturers of these sub-standard and hazardous electrical appliances and also to ensure strict enforcement of the laws in this regard for the safety of the consumers?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM); (a) Yes Sir, under the Household Electrical Appliances (Quality Control) Order 1981.

(b) During the raids recently conducted by the Directorate of Industries, Delhi Administration, 14 samples were seized from 13 traders and one manufacturer. Out of these 9 samples were found "unmarked" and 3 of the remaining 5 samples failed in the tests. 8 FIRs have been lodged against the traders from whom "un-mark" samples were seized. The Directorate of Industries is also holding meeting with the manufacturers and dealers in Delhi for strict compliance of the House-hold Electrical Appliances Quaity Control Order .

Chesterfield cigarettes

830. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Indian collaborators of Chesterfield cigarettes got permission from Government for the use of the name "Chesterfield"; and

(b) what is the total amount paid by the Indian collaborators to their foreign collaborators for the use of their trade mark?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M, ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) M/s. Godfrey Phillips India Limited, who are manufacturing cigarettes with the trade mark '"Chesterfield", have intimated that here is no direct or indirect consideration involved for the use of the trademark "Chesterfield" by them.

Commission on Judicial reforms

831. SHRI RAMANAND YADAV: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is fact that Government have constituted a Law Commission headed by Justice Desai, retired Supreme Court Judge, to go into the Judicial reforms;